2026:AHC: 165193-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1239/1990

अशोक कुमार .....अपीलार्थी(गण)

बनाम

राज्य .....प्रत्यर्थी(गण)

Translated Versionn. Not For legal Use.

और 1 संबंधित वाद

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता	: डी. स्वरूप, के कपूर, रवीन्द्र सिंह, विकास श्रीवास्तव
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: डी स्वरूप, रमेश कुमार, वी के चतुर्वेदी

निर्णय 20.07.2026 को सुरक्षित रखा गया
निर्णय 07.08.2026 को पारित किया गया

न्यायालय संख्या- 44

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा
माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

(द्वारा : न्यायमूर्ति अचल सचदेव)

1. आपराधिक अपील संख्या 1239/1990 अपर सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 268/1987 (राज्य बनाम अशोक कुमार एवं चार अन्य) में पारित दिनांक 12.06.1990 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थीगण अशोक कुमार, रामदास तथा कस्तूरी देवी को धारा 302/498-क भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दोषसिद्ध किया

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

गया, जबकि सह-अभियुक्त महराज सिंह तथा कुमारी सुमिता को उन्हीं आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।

2. आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1240/1990 सूचनादाता मेघ सिंह द्वारा उसी निर्णय में अंकित महराज सिंह तथा कुमारी सुमिता की दोषमुक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। आपराधिक पुनरीक्षण अभियुक्त महराज सिंह तथा कुमारी सुनीता की दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध इस आधार पर दाखिल किया गया था कि विचारण न्यायालय ने दोषमुक्ति का आदेश पारित करते समय साक्ष्य को ध्यान में लेने में असफल रहा तथा पुनरीक्षण याचिका में प्रतिपक्षी सं0 2 व 3 के विरुद्ध पारित दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

3. चूंकि दोनों कार्यवाहियां एक ही निर्णय से उद्भूत होती हैं तथा उनमें अतिव्यापी साक्ष्य सम्मिलित है, अतः इन्हें इस सम्मिलित निर्णय द्वारा निस्तारित किया जा रहा है।

4. अपील की लंबितता के दौरान अपीलार्थी सं0 2 रामदास तथा अपीलार्थी सं0 3 कस्तूरी देवी की मृत्यु हो गई, तथा दिनांक 18.07.2019 के आदेश द्वारा उनके संबंध में अपील उपशमित हो गई। तदनुसार अपील केवल अपीलार्थी सं0 1, अशोक कुमार, के संबंध में विद्यमान है, जबकि पुनरीक्षण अपनी संपूर्णता में विद्यमान है।

5. धारा 302 भा0द0सं0 के अधीन दोषसिद्धि पर, अभियुक्त-अपीलार्थीगण को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर रु0 2,000/- का अर्थदण्ड, अदायगी न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया। धारा 498-क भा0द0सं0 के अधीन दोषसिद्धि पर, प्रत्येक को एक वर्ष का कठोर कारावास तथा रु0 500/- का अर्थदण्ड, अदायगी न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया। दोनों धाराओं के अधीन दण्ड समवर्ती रूप से भुगतने का निर्देश दिया गया।

6. अपील के निस्तारण हेतु वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि सूचनादाता मेघ सिंह द्वारा दिनांक 27.07.1986 को अपराह्न 1.20 बजे थाना विजयगढ़, जनपद अलीगढ़ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई (तहरीर रिपोर्ट, प्रदर्श क-1; एफ0आई0आर0, प्रदर्श क-7)। यह अभिकथित किया गया कि उसकी पुत्री सुनीता का विवाह जून 1982 में ग्राम कौमरी निवासी रामदास के पुत्र अशोक कुमार से हुआ था, तथा विवाह में सूचनादाता की सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया गया था।

Translated Version Not For legal Use.

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

तत्पश्चात पति अशोक कुमार, ससुर रामदास तथा सास कस्तूरी देवी द्वारा अतिरिक्त दहेज के रूप में एक टेलीविजन तथा एक मोटरसाइकिल की मांग की गई, जिसे सूचनादाता पूरा नहीं कर सका, जिसके फलस्वरूप मृतका को प्रताड़ित किया गया। कुछ समय तक उसे अपने मायके जाने की अनुमति नहीं दी गई; बाद में सूचनादाता के अनुनय पर उसे मायके भेजा गया। सूचनादाता के पुत्र मनोज द्वारा सुनीता को इस आश्वासन पर वापस उसके ससुराल ले जाया गया कि अशोक कुमार का पिता टेलीविजन तथा मोटरसाइकिल की व्यवस्था कर देगा। दिनांक 30.06.1986 को मृतका के स्वयं के अनुरोध पर, उसे उसके भाई अनिल द्वारा वापस ग्राम कौमरी ले जाया गया। दिनांक 26.07.1986 को सूचनादाता को अपनी पुत्री का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उसे लिवा ले जाने का अनुरोध किया गया था तथा यह उल्लेख किया गया था कि उसके जीवन को खतरा है। इसे प्राप्त करने पर सूचनादाता, विवाह के मध्यस्थ राम सिंह के साथ, दिनांक 27.07.1986 को ग्राम कौमरी गया तथा लगभग दोपहर के समय अशोक कुमार, रामदास, कस्तूरी देवी तथा कुमारी सुमिता को घर के अंदर पाया, जहां मृतका का शरीर पहले से ही जल रहा था। सूचनादाता तथा राम सिंह को देखकर अभियुक्तगण भाग गए, तथा सुनीता का अर्धदग्ध शव घटनास्थल पर पड़ा हुआ पाया गया। रिपोर्ट राम सिंह द्वारा सूचनादाता के कथनानुसार लिखी गई तथा सूचनादाता द्वारा हस्ताक्षरित की गई; राम सिंह को घटनास्थल पर छोड़कर सूचनादाता रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु थाना विजयगढ़ गया।

7. एफ0आई0आर0 पंजीकृत होने पर, सिकंदराराव के सर्किल ऑफिसर, उपनिरीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के साथ, घटनास्थल पर पहुंचे। पंचायतनामा (प्रदर्श क-6), मुख्य चिकित्साधिकारी को पत्र, चालान लाश , चिकित्सा अधिकारी को पत्र (प्रदर्श क-12), पुलिस अधीक्षक को पत्र (प्रदर्श क-13), नक्शा नजरी (प्रदर्श क-16) तथा नमूना फर्द (प्रदर्श सं0 15) तैयार किए गए। मृतका के शव को सील करके पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया। घटनास्थल से अर्धदग्ध लकड़ी तथा वस्त्र बरामदगी फर्द (प्रदर्श क-15) के अंतर्गत बरामद किए गए। अभियुक्ता कस्तूरी देवी को दिनांक 28.07.1986 को गिरफ्तार किया गया, जिसकी प्रविष्टि सामान्य डायरी सं0 20 दिनांक 28.07.1986 अपराह्न 4.00 बजे में की गई। तत्पश्चात विवेचना क्षेत्राधिकारी सुनील सी0 वार्ष्णेय द्वारा अपने हाथ में ली गई, जिन्होंने साक्षियों के कथन अंकित किए, मृतका द्वारा अपने माता-पिता को लिखे गए पत्रों को कब्जे में लिया, आगे का नक्शा (प्रदर्श क-16) तैयार किया, तथा विवेचना पूर्ण करने पर

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

समस्त पांचों अभियुक्तों – अशोक कुमार, रामदास, कस्तूरी देवी, महराज सिंह तथा बरीलाल की पुत्री एवं अशोक कुमार की भतीजी कुमारी सुमिता – के विरुद्ध आरोप-पत्र (प्रदर्श क-17) प्रस्तुत किया।

8. अभियोजन पक्ष द्वारा सात साक्षियों को परीक्षित किया गया। पी0डब्ल्यू0-1 मेघ सिंह, सूचनादाता तथा मृतका के पिता, ने तहरीर रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) साबित किया। पी0डब्ल्यू0-2 राम सिंह, तहरीर रिपोर्ट के लेखक तथा एफ0आई0आर0 दर्ज कराए जाने से तुरंत पूर्व घर पर पाई गई स्थिति के साक्षी, ने इसकी पुष्टि किया। पी0डब्ल्यू0-3 डॉ0 राजीव अग्रवाल ने दिनांक 28.07.1986 को मृतका का पोस्टमार्टम परीक्षण किया। पी0डब्ल्यू0-4 रमेश चंद्र, विवेचक उपनिरीक्षक के साथ घटनास्थल पर गए तथा पंचायतनामा कार्यवाही पर अपने हस्ताक्षर साबित किए। पी0डब्ल्यू0-5 अभय कुमार, दिनांक 27.07.1986 को थाना विजयगढ़ पर तैनात कांस्टेबल लिपिक, ने एफ0आई0आर0 (प्रदर्श क-7) तथा संगत सामान्य डायरी प्रविष्टि साबित किया पी0डब्ल्यू0-6 उपनिरीक्षक ओम प्रकाश शर्मा ने पंचायतनामा तैयार किया तथा मृतका का पंचायतनामा किया। पी0डब्ल्यू0-7, विवेचना पूर्ण करने वाले क्षेत्राधिकारी, ने आरोप-पत्र (प्रदर्श क-17) दाखिल किया, नक्शा (प्रदर्श क-16) साबित किया, तथा सूचनादाता, राम सिंह एवं उपनिरीक्षक शर्मा के कथन अंकित किए।

9. अपने मुख्य परीक्षण में पी0डब्ल्यू0-1 ने एफ0आई0आर0 में उल्लिखित अभिकथनों की पुष्टि की तथा यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृतका को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर बार-बार प्रताड़ित किया गया। पी0डब्ल्यू0-2 राम सिंह, जिसने अशोक कुमार तथा मृतका के विवाह में मध्यस्थता की थी, ने इस बिंदु पर अभियोजन के मामले का समर्थन किया। मांग तथा अभिकथित प्रताड़ना का तथ्य अखंडित रहा है। तथापि, अभियुक्त महराज सिंह अथवा कुमारी सुमिता को सामान्य अभिकथनों से परे कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है, तथा यह संभावना अपवर्जित नहीं की जा सकती कि उन्हें उन अपीलार्थियों के साथ, जिन पर अभियोग का प्रत्यक्ष भार पड़ा, मिथ्या रूप से फंसाया गया हो।

10. सिद्धांत *" फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ऑम्निबस* (एक बात में असत्य, सब बातों में असत्य) को भारत में साक्ष्य के नियम के रूप में स्वीकृति कभी नहीं मिली है; यह, अधिक से अधिक, सावधानी का एक नियम है, तथा इसने विधि के नियम का दर्जा प्राप्त नहीं किया है। यह

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

न्यायालय का कर्तव्य बना रहता है कि वह भूसी से दाना अलग करे, प्रत्येक अभियुक्त के संबंध में साक्षी की साक्ष्य के उतने भाग को विश्वसनीय मानते हुए स्वीकार करे जितना विश्वसनीय पाया जाए तथा केवल उस भाग को अस्वीकार करे जो विश्वसनीय न हो; ऐसा पृथक्करण असंभव होने पर ही साक्ष्य को समग्रतः अस्वीकार किए जाने की आवश्यकता होती है (***राजस्थान राज्य बनाम कालकी, (1981) 2 एस0सी0सी0 752; उगर अहीर बनाम बिहार राज्य, ए0आई0आर0 1965 एस0सी0 277)***। इस आधार पर, महराज सिंह तथा कुमारी सुमिता के मिथ्या रूप से फंसाए जाने की संभावना, बिना अधिक के, पी0डब्ल्यू0-1 तथा पी0डब्ल्यू0-2 की साक्ष्य को, जहां तक वह अपीलार्थी अशोक कुमार तथा मृतक अपीलार्थीगण से संबंधित है, दूषित नहीं करती, जिनकी दोषिता का परीक्षण नीचे विवेचित चिकित्सीय एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर स्वतंत्र रूप से किया जाना है।

11. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर, अभियुक्तों के कथन धारा 313 दं0प्र0सं0 के अधीन अंकित किए गए, जिसमें उन्होंने अभिकथनों से इनकार किया तथा मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया। बचाव पक्ष में दो साक्षियों की परीक्षा कराई गई: डी0डब्ल्यू0-1 एम0पी0 शुक्ला, टेलीफोन निगम में उप-अभियंता (योजना), तथा डी0डब्ल्यू0-2 विजयपाल सिंह, जल्ला सिंह का पुत्र, ग्राम कौमरी निवासी तथा सूचनादाता का दामाद। उल्लेखनीय है कि डी0डब्ल्यू0-2, विवाह संबंध से सूचनादाता के परिवार से जुड़ा होते हुए भी, बचाव पक्ष के घटना-वृतांत के समर्थन में अभिसाक्ष्य दिया।

12. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने महराज सिंह तथा कुमारी सुमिता को यह अभिनिर्धारित करते हुए दोषमुक्त किया कि उन्हें न तो दहेज की मांग से और न ही मृतका की प्रताड़ना से जोड़ने वाला कोई साक्ष्य है। अशोक कुमार, रामदास तथा कस्तूरी देवी को धारा 302/498-क भा0द0सं0 के अधीन दोषसिद्ध किया गया तथा उपर्युक्तानुसार दण्डित किया गया।

13. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मृतका की मृत्यु आकस्मिक थी, तथा न तो कोई अनुचित कृत्य हुआ और न ही अतिरिक्त दहेज की कोई मांग थी। डी0डब्ल्यू0-2 विजयपाल सिंह की साक्ष्य पर विश्वास किया गया है, जिसने अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के समय उसने रामदास के घर से धुआं उठते देखा, कस्तूरी देवी को गौशाला की दिशा से आते देखा, तथा कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया गया; उसे तोड़कर खोलने पर, मृतका धुएं के बीच मृत पाई गई,

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

जबकि रामदास घर पर नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया है कि एफ0आई0आर0 सूचनादाता के इशारे पर पूर्व-दिनांकित की गई, जिसने नायब तहसीलदार पर प्रभाव डाला, तथा यह कि अभियुक्तों को मिथ्या रूप से फंसाया गया है।

14. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए0जी0ए0 तथा पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि मृतका का अर्धदग्ध शव अभियुक्तों के अनन्य कब्जे वाले घर के भीतर से बरामद हुआ, तथा अभियुक्तों ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि मृतका उस दशा में कैसे पहुंची, न ही मृतका के पिता को किसी दुर्घटना की कोई सूचना दी गई। आगे यह निवेदन किया गया है कि मृतका ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व अपने माता-पिता को एक पत्र (प्रदर्श क-2) लिखा था जिसमें अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना की शिकायत की गई थी – यह पत्र, जो सूचनादाता को उसकी मृत्यु से एक दिन पूर्व प्राप्त हुआ, जिसकी लेखकता बचाव पक्ष द्वारा अस्वीकृत नहीं की गई है।

15. डॉ0 राजीव अग्रवाल (पी0डब्ल्यू0-3) ने दिनांक 28.07.1986 को जिला चिकित्सालय, अलीगढ़ में पोस्टमार्टम परीक्षण किया तथा शव को मुष्टियोद्धा मुद्रा में पाया, जिसके मुंह तथा नाक से झाग निकल रहा था। उन्होंने गहरे, मृत्यु-पूर्व दाह चोटों को नोट किया जिनके किनारों पर लालिमा की रेखा थी, तथा यह मत व्यक्त किया कि मृत्यु मृत्यु-पूर्व दाह से उत्पन्न शॉक तथा श्वासावरोध के कारण हुई।

16. मुष्टियोद्धा (मुक्केबाज की) मुद्रा न्यायालयिक आयुर्विज्ञान में एक सुविज्ञ लक्षण है (मोदी की मेडिकल जुरिसप्रूडेंस एण्ड टॉक्सिकोलॉजी)। यह ऊष्मा-प्रेरित स्कंदन तथा तत्पश्चात फ्लेक्सर पेशी समूहों के, जो एक्सटेंसर की तुलना में अधिक स्थूल होते हैं, संकुचन के परिणामस्वरूप होती है, जिससे अंग मुड़कर मुक्केबाज जैसी मुद्रा – कोहनी व घुटने मुड़े हुए, मुट्ठियां भिंची हुई – ग्रहण कर लेते हैं। अपने आप में, मुष्टियोद्धा मुद्रा एक ऊष्मा-कलाकृति है तथा यह तब भी हो सकती है जब दाह प्रारंभ होते समय व्यक्ति जीवित रहा हो अथवा पहले ही मृत हो चुका हो; अकेले यह केवल इतना सिद्ध करती है कि शव तीव्र ऊष्मा के अधीन रहा, न कि यह कि दाह मृत्यु-पूर्व था। इस मामले में इसका साक्ष्यिक मूल्य पी0डब्ल्यू0-3 द्वारा अंकित अन्य लक्षणों के साथ मिलाकर पढ़े जाने से उत्पन्न होता है – विशेषतः, दाह घावों के किनारों पर लालिमा की रेखा (एरिथेमा/वाइटल रिएक्शन), तथा शव-परीक्षा रिपोर्ट में अंकित श्वासनली में कार्बन कणों की अनुपस्थिति। इस प्रकार

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

की लालिमा की रेखा एक जीवित संवहनी अनुक्रिया को प्रतिबिंबित करती है – रक्त तब भी परिसंचरित होकर चोट पर अनुक्रिया कर रहा था – तथा न्यायालयिक व्यवहार में यह विश्वसनीय संकेतक माना जाता है कि दाह मृत्यु से पूर्व हुआ, न कि मृत्यु-पश्चात दाह जिसमें ऐसी कोई वाइटल रिएक्शन नहीं दिखती। जहां, जैसा यहां है, शव-परीक्षा रिपोर्ट में भी गहरे मृत्यु-पूर्व दाह को मृत्यु का कारण अंकित किया गया है, तथा ऐसा कोई कालिख-रहित क्षेत्र अथवा अन्य लक्षण नहीं है जो यह सुझाव दे कि अग्नि पहले से मृत शव पर लगाई गई थी, वहां संपूर्ण चिकित्सीय साक्ष्य बचाव पक्ष द्वारा सुझाए गए आकस्मिक, मृत्यु-पश्चात अग्नि-सम्पर्क के बजाय मृत्यु-पूर्व, हत्यात्मक दाह के निष्कर्ष का समर्थन करता है। न्यायालयों ने ऐसे निष्कर्षों को, जब उपचार करने वाले अथवा शव-परीक्षक चिकित्सक की मौखिक साक्ष्य से संपुष्ट हों, इस प्रश्न पर सबल चिकित्सीय साक्ष्य के रूप में सदैव स्वीकार किया है; अपीलार्थी ने न तो पी0डब्ल्यू0-3 की प्रतिपरीक्षा कर लालिमा-रेखा संबंधी निष्कर्ष अथवा मृत्यु-कारण मत को खंडित किया है, न ही अपीलार्थी ने मृत्यु-पश्चात अथवा आकस्मिक अग्नि के सिद्धांत के समर्थन में स्वयं कोई चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत की है।

17. मृतका की मृत्यु अभियुक्तों के घर के भीतर एक कमरे में हुई, जिस तक प्रासंगिक समय पर पहुंच उस घर के निवासियों तक ही सीमित थी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 उपबंधित करती है कि "जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में हो, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होगा," तथा धारा से संलग्न दृष्टांत (ख) – बिना टिकट यात्रा करते पाए गए व्यक्ति का मामला, जहां वैध टिकट रखने का तथ्य उस व्यक्ति के अपने विशेष ज्ञान में होता है – उस प्रकार के तथ्य को दृष्टांतित करता है जिसे यह उपबंध संबोधित करने हेतु है: दोषिता का चरम तथ्य नहीं, अपितु एक गौण तथ्य जिसे यथार्थतः केवल संबंधित व्यक्ति ही स्पष्ट करने की स्थिति में होता है।

18. उच्चतम न्यायालय ने ***त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2006) 10 एस0सी0सी0 681*** में, इस तर्क को पत्नी की उसके ससुराल में हुई अस्वाभाविक मृत्यु के मामले में लागू किया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह विशुद्ध नियम कि दोषिता साबित करने का भार सर्वदा अभियोजन पर रहता है, को हर मामले में यांत्रिक रूप से लागू किए जाने वाले जीवाश्मीकृत सिद्धांत के रूप में नहीं माना जाना चाहिए; जहां हत्या जैसा अपराध घर की एकांतता में किया

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

गया हो, वहां अभियोजन से यह यथार्थतः अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह उतनी ही गुणवत्ता एवं मात्रा की साक्ष्य प्रस्तुत करे जितनी खुले में देखी गई घटना के मामले में की जाती है, तथा उस पर भार, इस अर्थ में, "तुलनात्मक रूप से हल्के स्वरूप का" होता है। तदनुरूप, धारा 106 घर के निवासियों पर यह भार डालती है कि वे मृत्यु कैसे हुई इसका सुसंगत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। निवासी केवल इस आधार पर मौन रहकर स्वयं को उन्मुक्त नहीं कर सकते कि भार सदैव पूर्णतः अभियोजन पर रहता है; यदि वे कोई स्पष्टीकरण नहीं देते, अथवा मिथ्या स्पष्टीकरण देते हैं, तो वह मौन अथवा मिथ्यात्व उनके विरुद्ध परिस्थितियों की श्रृंखला को सुदृढ़ करने वाली एक अतिरिक्त कड़ी बन जाता है। यह बल देने योग्य है कि यह संपूर्ण अभियोग को साबित करने के भार को, जो सर्वदा अभियोजन पर बना रहता है, उलटता नहीं है, तथा धारा 106 अभियोजन को उन आधारभूत आपराधिक-संकेतक परिस्थितियों को स्थापित करने के दायित्व से मुक्त नहीं करती – यहां, यह कि मृतका की मृत्यु अस्वाभाविक, मृत्यु-पूर्व दाह से हुई, अभियुक्तों के अधिभोग वाले कमरे के भीतर, उसके पिता को उसके जीवन की आशंका दर्ज करने वाला पत्र प्राप्त होने के तुरंत पश्चात। इन आधारभूत तथ्यों के स्थापित हो जाने पर ही उन्हें स्पष्ट करने का साक्ष्यिक भार उन व्यक्तियों पर स्थानांतरित होता है जो उन्हें स्पष्ट करने की विशिष्ट स्थिति में हैं।

19. इसे ***शरद बिरधीचंद सारडा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एस0सी0सी0 116*** के सिद्धांत से सुदृढ़ता मिलती है, जहां उच्चतम न्यायालय ने, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर दोषसिद्धि को शासित करने वाली पांच शर्तें ("पंचशील") – कि परिस्थितियां पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए, केवल दोषिता के अनुरूप होनी चाहिए, दोषिता से भिन्न प्रत्येक युक्तियुक्त परिकल्पना को अपवर्जित करनी चाहिए, प्रत्येक निश्चायक रूप से साबित होनी चाहिए, तथा साथ मिलकर एक पूर्ण, अखंडित श्रृंखला बनानी चाहिए – निर्धारित करते हुए, यह भी अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत मिथ्या बचाव अथवा मिथ्या स्पष्टीकरण को, यदि अन्य कड़ियां अन्यथा सबलतापूर्वक स्थापित हों, तो उस श्रृंखला को सुदृढ़ करने वाली एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है; मिथ्या अभिवाक् अकेले किसी लुप्त कड़ी का स्थानापन्न नहीं हो सकता, किंतु यह अन्यथा पूर्ण श्रृंखला को समाप्त कर सकता है।

20. इन सिद्धांतों को वर्तमान तथ्यों पर लागू करने पर: डी0डब्ल्यू0-2 के माध्यम से उठाया गया आकस्मिक अग्नि का स्पष्टीकरण – कि मृतका अंदर से बंद कमरे में मृत पाई गई, जिसमें

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

अभियुक्तों में से कोई उपस्थित नहीं था – यह स्पष्ट करने में असफल रहता है कि सूचनादाता को अभियुक्तों से किसी दुर्घटना की कोई सूचना क्यों नहीं मिली, जो इस संस्करण के अनुसार अग्नि की खोज करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे; मृतका के दहेज-प्रताड़ना की शिकायत करने वाले पत्रों को, जिनमें उसकी मृत्यु से मुश्किल से एक दिन पूर्व लिखा गया पत्र भी सम्मिलित है, बचाव पक्ष द्वारा अनदेखा क्यों किया गया; अथवा, यदि अग्नि आकस्मिक थी तथा स्वयं परिवार द्वारा खोजी गई थी, तो शव को उस दशा में सूचनादाता द्वारा स्वयं की पहल पर खोजे जाने हेतु क्यों छोड़ा गया, न कि अभियुक्तों द्वारा उसे अथवा पुलिस को सूचित किया गया। मृत्यु-पूर्व, हत्यात्मक दाह के शव-परीक्षा निष्कर्ष के विरुद्ध पढ़े जाने पर, बचाव पक्ष के वृतांत में यह त्रुटि कोई परिधीय चूक नहीं है अपितु उसी तथ्य से संबंधित है, जिसे धारा 106 अभियुक्तों के विशेष ज्ञान में रखती है – कि मृतका उनके घर के भीतर कैसे जल गई। इस अभिलेख पर, वह भार वहन नहीं किया गया है, तथा बचाव पक्ष का संस्करण, अभियोजन के मामले को विस्थापित करने के बजाय, शरद बिरधीचंद सारडा के अर्थ के भीतर अभियुक्तों के विरुद्ध एक अतिरिक्त कड़ी बन जाता है।

21. महराज सिंह तथा कुमारी सुमिता के संबंध में, विचारण न्यायालय ने ऐसी कोई सामग्री नहीं पाई जो उन्हें दहेज की मांग अथवा मृतका की प्रताड़ना से जोड़ती हो, तथा उनकी दोषमुक्ति अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य के युक्तियुक्त मूल्यांकन पर आधारित है। उस दोषमुक्ति को चुनौती अपील के मार्ग से नहीं, अपितु सूचनादाता, एक निजी पक्ष, की ओर से पुनरीक्षण के मार्ग से दी गई है, तथा हस्तक्षेप की उपलब्ध परिधि तदनुरूप और भी संकीर्ण है। दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण में, न्यायालय साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर दोषमुक्ति को दोषसिद्धि में परिवर्तित करने हेतु अपील न्यायालय के रूप में नहीं बैठता; हस्तक्षेप उन श्रेणियों तक सीमित है जैसे कि जहां विचारण न्यायालय को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न रहा हो, जहां उसने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली साक्ष्य को गलत ढंग से अवरुद्ध किया हो, अथवा जहां निष्कर्ष विकृत हो अथवा अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर कोई निष्कर्ष ही न हो – इनमें से कोई भी यहां प्रदर्शित नहीं होता ***(अकालू अहीर बनाम रामदेव राम, (1973) 2 एस0सी0सी0 583)।***

22. उपर्युक्त कारणों से, आपराधिक अपील सं0 1239/1990, जो अपीलार्थी सं0 1, अर्थात् अशोक कुमार, के संबंध में विद्यमान है, खारिज की जाती है, तथा उसके विरुद्ध धारा 302/498-क

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

भा0द0सं0 के अधीन अभिलिखित दोषसिद्धि तथा दण्डादेश की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी सं0 1, यदि जमानत पर है, तो तुरंत आत्मसमर्पण करे। जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं।

23. जहां तक आपराधिक अपील सं0 1239/1990 में अपीलार्थी सं0 2 व 3, अर्थात् रामदास तथा श्रीमती कस्तूरी देवी का संबंध है, उनकी अपील दिनांक 18.07.2019 के आदेश द्वारा उनकी मृत्यु के कारण अपील की लंबितता के दौरान पहले ही उपशमित की जा चुकी है, तथा उनके प्रकरणों में गुणदोष पर किसी अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं है।

24. जहां तक आपराधिक पुनरीक्षण सं0 1240/1990 का संबंध है, यह भी खारिज किया जाता है तथा अभियुक्त-प्रतिपक्षी सं0 2 व 3, अर्थात् महराज सिंह तथा कुमारी सुमिता की दोषमुक्ति की पुष्टि की जाती है।

25. उपर्युक्त आपराधिक अपील तथा संबद्ध आपराधिक पुनरीक्षण तदनुसार निस्तारित किए जाते हैं।

26. इस निर्णय की एक प्रति अनुपालनार्थ संबंधित न्यायालय को, विचारण न्यायालय के अभिलेख सहित, निर्धारित अवधि के भीतर प्रमाणित की जाए।

27. इस निर्णय की एक प्रति संबद्ध वाद के अभिलेख पर भी रखी जाए।

7 अगस्त, 2026

वी के गी

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा)

Translated Version. Not For legal Use.

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"